3 पत्रकारों का महाकुंभ 12 को आलोट में

5 देवेंद्र फडणवीसः पार्षद से सीएम तक का सफर

7 डॉ. हिमादी को सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 31 प्रति सोमवार, 9 दिसंबर 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

विष्णुदेव साय सत्ता में एक वर्ष पहले आये और बदल दी जनहित और जनकल्याण के फैसलों से प्रदेश की तस्वीर

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

प्रदेश की जनता के सामने मुख्यमंत्री पेश करेंगे 365 दिनों के कार्य का रिपोर्ट कार्ड, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बंद की गई प्रमुख योजना होगी फिर से शुरू।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का लगभग एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने चला है। महज छह दिन बाद प्रदेश सरकार को सत्ता में आने के 365 दिन पूरे हो जायेंगे। खास बात यह है कि इन एक वर्ष में साय सरकार ने जनहित और जनकल्याण के ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले किये हैं जिसने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया है। इसी क्रम में पिछले दिनों दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही सरकार का एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। विस्तृत कवर स्टोरी पेज 2 पर...

विकसित छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा अहम योगदान विस्तृत स्पेशल खबर पेज 2 पर

मध्यप्रदेश में शुरू हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सियासी हलचल

क्या भ्रष्टाचार के आरोप और लोकायुक्त की जांच के आरोपी रह चुके भूपेंद्र सिंह पर भरोसा दिखाएगी भाजपा?

...या फिर दिखाएगी "संगठन सर्वोपरि" रखने वाले वी.डी. शर्मा पर भरोसा?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए अलग-अलग स्तर पर चयन समिति का गठन कर कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग-अलग दलों के नेता अलग-अलग नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष के सुझा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपने जा रही है। या अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो भले ही वीडी शर्मा के शुरुआती कार्यकाल में कार्यशैली को लेकर खींचतान हुई हो लेकिन समय के साथ वीडी शर्मा ने पार्टी को संभाला और सभी नेताओं को एकजुट कर आगे बढ़े। यही कारण है कि आज भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सशक्त पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

कई नामों पर हो रही चर्चा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश के सक्रिय नेता अपने चहेतों का नाम आगे बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने करीबी नेताओं का नाम लेकर दिल्ली तक पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दो दिन पहले उज्जैन आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन और मालवा के नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेंद्र सिंह को बतौर प्रदेश अध्यक्ष नाम आगे बढ़ाया है। जबकि देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर सहित गोपाल भार्गव का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। (शेष पेज 3 पर)

बार-बार बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ाकर

आखिर कौन हैं वो कांग्रेसी जो कमलनाथ और कांग्रेस की साख पर लगा रहे हैं बट्टा?

(विस्तृत पेज 8 पर)

प्रदेश की जनता के सामने 365 दिनों के कार्य का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

(पेज 1 से जारी) मुख्यमंत्री साय के अनुसार साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। एक साल पूरा करने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने कहा "एक साल में हमारी सरकार की जो भी उपलब्धि है, सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बीते एक साल के दौरान जो विकास कार्य किए हैं। हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। दिल्ली दौरे के बारे में जानकारी देते हुए सीएम साय ने कहा- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम लोगों ने दिल्ली आकर उन्हें आमंत्रण दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निमंत्रण स्वीकार कर समारोह में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को बैठक में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई है।

नक्सलियों पर शिकंजा कसना है मुख्य उद्देश्य

वहीं, नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस तरह से पिछले एक वर्ष से उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं।" बता दें कि नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में डीआरजी नारायणपुर के हेड कॉन्स्टेबल बिरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गए थे। शहीद बिरेंद्र कुमार सोरी नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया गया था। सीएम ने कहा- मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत पुण्यात्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हर देशभक्त का त्याग और बलिदान, हमें देश की रक्षा के प्रति प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्र आपकी वीरता और समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा।

13 दिसंबर को सीएम बने थे विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 03 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। तब राज्य में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। हार के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विष्णुदेव साय के साथ विजय शर्मा और अरुण साव ने डेप्युटी सीएम पद की शपथ ली थी।

साय सरकार में हो सकता है कैबिनेट विस्तार

छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी सरकार ने पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। विष्णुदेव साय की सरकार इससे पहले भी भूपेश बघेल की कई योजनाओं का नाम बदल चुकी है। जबकि कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने तीरथ बरत योजना का नाम बदल दिया है। इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 2012 में तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने की थी। उसके बाद 2018 में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ था। जिसके बाद भूपेश बघेल की सरकार ने कई योजनाओं को बंद किया था और उनके नाम भी बदल दिए थे।

बघेल ने बंद कर दी थी योजना

2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसके बाद भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का नाम बदलर तीरथ बरत योजना कर दिया है। हालांकि जानकारी के अनुसार, 2019 से 2023 तक इस योजना के तहत कोई यात्राएं नहीं की गई थीं।

सरकार ने फंड भी जारी किया

तीरथ बरत योजना का नाम बदलने के साथ ही राज्य सरकार ने इस योजना के लिए फंड की भी व्यवस्था शुरू की है। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए साल 2024-2025 के लिए अनुपूरकरक बजट में 25 करोड़ रुपये के फंड का भी इंतजाम किया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है जहां निशक्तजन शब्द लिखा गया है वहां दिव्यांग शब्दों का उपयोग किया जाए।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

2012 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के सीएम रमन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को पूरे करने का मकसद राज्य के सीनियर सिटीजन को धार्मिक और अध्यात्मिक यात्रा करना था। सरकार वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाती थी।

विकसित छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा अहम योगदान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरामय छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एम्स आडिटोरियम में रिमोट का बटन दबाकर 100 दिनों तक चलने वाले राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिमोट का बटन दबाकर निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1 हजार रूपए की राशि के आनलाइन ट्रांसफर करने की भी शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को निक्षय निरामय की शपथ भी दिलाई। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 100 दिनों तक राज्य में टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीजों की पहचान की जाएगी और उनका उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में राज्य के वृद्धजनों का भी स्वास्थ्य जांच और उपचार शामिल है।

इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत के साथ ही साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य रखा गया है और इस

लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो रहा है। बीते 12 महीनों में हमने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो ऐसे विषय हैं जो सीधे-सीधे राज्य और राष्ट्र के विकास से जुड़े हुए हैं। जब हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वे राष्ट्र के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे पाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के साथ ही सभी चिकित्सकों ने भी प्रदेश में चलाए जा रहे स्वास्थ्य अभियानों में हमेशा तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। अनेक दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन के साधनों की कमी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अंदरुनी गांवों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अनेक दुर्गम गांवों तक पहुंचने के लिए लंबी-लंबी पदयात्राएं कीं, नदी-नालों को भी पार किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में आप लोगों का यह जज्बा सेना के किसी जवान के जज्बे से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य निरामय छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की शुरूआत की जा रही है, मेकाहारा जैसे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने के लिए नए अस्पताल भवन तैयार किए जा रहे हैं और चिकित्सकों की लगातार भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए मैदानी अमलों, विशेषकर मितानिन बहनों की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर निक्षय पोषण योजना के हितग्राहियों को आनलाइन डीबीटी के जरिए राशि प्रदान करने की शुरूआत करने के लिए धन्यवाद दिया। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हाथों से हितग्राहियों को पोषण आहार, हियरिंग एड, वाकर और वाकिंग स्टिक प्रदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मितानिन बहनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर आरंग विधायक खुशवंत साहेब, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव प्रियंका शुक्ला एवं एमडी एनएचएम विजय दयाराम के. भी उपस्थित थे।

क्या भ्रष्टाचार के आरोप और लोकायुक्त की जांच के आरोपी रह चुके भूपेंद्र सिंह पर भरोसा दिखाएगी भाजपा? ...या फिर दिखाएगी "संगठन सर्वोपरि" रखने वाले वी.डी. शर्मा पर भरोसा?

(पेज 1 का शेष)

अभी तक सामने आए सभी नामों पर बारीकि से नजर डाले तो देखने में आता है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को छोड़ सभी नेता प्रदेश अध्यक्ष की काबिलियत रखते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, सागर और खुरई में उनकी गुंडई ने प्रदेश भाजपा को पहले भी उनके चयन के लिए कठघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे में अब भाजपा दोबारा उनके नाम पर विचार करेगी यह तो संभव नहीं। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के बारे में उन्होंने कहा था कि "पार्टी स्वीकार करे या ना करे मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा", इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सिंधिया और उनके करीबी भूपेंद्र सिंह के अध्यक्ष बन जाने के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यही नहीं अगर भाजपा की अपनी प्रतिकृति अनुसार कार्यशैली को आगे बढ़ाना है तो भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से बाहर निकलना होगा।

महाकाल लोक से लेकर मारपीट और अवैध वसूली के हैं आरोप

पूर्वमंत्री भूपेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं। यह बात सभी लोगों को पता है ऐसे में भूपेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के लिए शिवराज सिंह चौहान खुद भी काफी

जोर लगा रहे हैं। और वे लगातार भूपेंद्र सिंह के नाम की चर्चा राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं से कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं भूपेंद्र सिंह के नाम पर इनकार कर दिया है। उसकी सबसे बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह के ऊपर महाकाल लोक और नगरीय निकाय में किए गए भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

महाकाल लोक पर उठा था विवाद

मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंधी के दौरान महाकाल लोक परिसर में क्षति को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा था कि कांग्रेस को उन्हें ठोस सबूत देना चाहिए या सार्वजनिक माफी जारी करनी चाहिए। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर कहा कि शिवराज सरकार ने 2017 में महाकाल लोक के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था,

जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

उपमुख्यमंत्री के सामने लगाए थे आरोप

शिवराज सरकार में गृह, परिवहन एवं नगरीय प्रशासन मंत्री रहे खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने पहली दफा जिला योजना समिति की बैठक में खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी-आईजी की अनुमति के बगैर कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ लोगों के मोबाइल की सीडीआर निकाल रहे हैं। ऐसे मामले 05 महीने से सामने आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को धमकियां देकर बताया है कि आपने कुछ लोगों से फोन पर इस तरह की बातें की हैं। जिनके साथ ऐसा हुआ है, उन लोगों ने मुझे आकर बताया है। भूपेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने बैठक में सागर एसपी विकास शाहवाल ने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सिंह ने कहा कि सफाई नहीं चाहिए है, गृहमंत्री रहा हूं मुझे सब पता है। आप तो यह बताइए कि ऐसा किसकी परमिशन से हो रहा है और क्यों हो रहा है?

भूपेंद्र सिंह पर दर्ज हुआ था आय से अधिक संपति का मामला

लोकायुक्त संगठन ने कांग्रेस की शिकायत पर तत्कालीन प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और कांग्रेस के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टण्डन ने इस संबंध में शिकायत की थी। कांग्रेस नेताओं ने 30 मई 2023 को चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों, एडीआर रिपोर्ट एवं खसरा अभिलेखों के आधार पर अनुपातहीन संपत्ति होने के आरोप भूपेंद्र सिंह पर पत्रकारवार्ता में लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि मंत्री भूपेन्द्र सिंह और उनके परिवारजनों ने 10 साल के भीतर लगभग 46 करोड़ की अकूत संपत्ति अर्जित की है। ये भी कहा था कि आश्चर्यजनक रूप से वर्ष 2018-19 में लगभग 07 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने संबंधी रिटर्न प्रस्तुत करना भी अर्जित अनुपातहीन एवं आय से अधिक संपत्ति को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं की इस शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच क्रमांक 0035/ई/ 2023-24 के मामले में पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त से 08 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट मांगी है।

भूपेंद्र सिंह के कहने पर बदला था लोकायुक्त डीजी

शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेताओं में शामिल भूपेंद्र सिंह ने तत्कालीन लोकायुक्त डीजी कैलाश मकवाना पर दबाव बनाकर अपना केस रफा दफा करने का प्रयास किया था। लेकिन मकवाना चूंकि एक ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, ऐसे में उन्होंने पूरे मामले की बारीकी से जांच करवाई। जांच में भूपेंद्र सिंह के दोषी पाए जाने की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में लोकायुक्त डीजी का तबादला कर दिया। लेकिन अब वहीं मकवाना प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर पदस्थ हुए।

दलित परिवार की हत्या में भी लगे थे आरोप

बरोदिया नोनागिर दलित हत्याकांड में में परिवार की तरफ से आरोपियों को भूपेंद्र सिंह द्वारा बचाने के आरोप लगाए थे। मामला और संदिग्ध नजर इसलिए आता है कि आरोप लगाने वाली बहन अंजना अहिरवार की हत्या करवा दी गई थी जिसे आत्महत्या की शक्ल दी गई थी।

पत्रकारों का महाकुंभ 12 जनवरी को आलोट में

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में 12 जनवरी 22025 रविवार को प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के प्रदेश अध्यक्ष दलजीतसिंह गुरुदत्ता, महानियंत्रक केसी यादव, प्रदेश महासचिव अल्ताफ मसूरी, प्रदेश सचिव प्रमोद बरसले, प्रदेश संयुक्त सचिव दिनेश जागलवा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शर्मा, संरक्षक उपेन्द्र यादव, ताल इकाई अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा उपस्थित रहेंगे।

विगत 26 सालों से दिनेश जागलवा, फिरोज खान, कपिल जागलवा, नीलेश जागलवा की टीम यह सम्मेलन को अच्छी तरह से आयोजित करते हैं। इस सम्मेलन में शिक्षा खेलकूद सामाजिक कार्यक्रमों में जिन्होंने आलोट शहर का नाम रोशन किया है। उनका सम्मान भी किया जायेगा। इस सम्मेलन में मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार, रतलाम, बदनावर, टिमरनी, बैतूल, सिवनी, छपारा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, आष्टा, शाजापुर, अलीराजपुर, कटनी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पत्रकार उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में सभी पत्रकारों का शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। पत्रकारों के इस महाकुंभ की पूर्णाहुति के लिये टिमरनी से पत्रकारों का जत्था आलोट जायेगा। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बेहद चिंताजनक

बांग्लादेश में 77-78 वर्षों के बाद इतिहास दोहराया जा रहा हैं। वही चीखें, वही रुह कापता करुण क्रंदन, वही आंसुओं से डबडबाई आंखें, वहीं पाशवी बलात्कार के बाद फेंकी गई बिभत्स लाशें, वही उजड़े हुए- जलते हुए घर, वही खामोश, मूकदर्शक बना स्थानीय प्रशासन, और वही असहाय हिंदू। विभाजन के समय का दृश्य पूरे, बांग्लादेश में पुनः प्रस्तुत हो रहा हैं। वैसे बांग्लादेश के लिए यह नया नहीं हैं। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाह, जनरल टिक्का खान ने 'ऑपरेशन सर्चलाइट' चलाकर हिंदुओं का वंशच्छेद प्रारंभ किया था। 23 मार्च 1971 को चालू हुए इस आक्रमण में, तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान (अभी का बांग्लादेश) के 30 लाख हिंदुओं को मात्र कुछ ही महीनों में, पाशवी तरीके से मार दिया गया था। चार लाख से ज्यादा जवान बहू - बेटियों पर निर्मम बलात्कार किए गए थे। इन सब के बाद भी, बांग्लादेश का साहसी हिंदू, जिजीविषा के साथ डटा रहा। उसने अपने मातृभूमि को नहीं छोड़ा।

बांग्लादेश के हिंदुओं के इस अदम्य साहस से चिढ़ कर, वहां के अतिवादी मुसलमानों ने 05 अगस्त 2024 से हिंदुओं के जिनोसाइड को दोहराना प्रारंभ कर दिया हैं। जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ छात्रों का आंदोलन, प्रारंभ में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में था। अनेक बाहरी ताकते इस आंदोलन में शामिल थी। किंतु जैसे ही 5 अगस्त को शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश से पलायन किया, वैसे ही यह सारा आंदोलन हिंदू-बौद्ध नागरिकों के विरोध में चला गया। तब से चार महीने होते आए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 अगस्त से आज तक, बांग्लादेश के हिंदुओं ने रात को ठीक से नींद नहीं ली हैं। हजारों हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है। इनमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध उद्योगपति, कलाकार, गायक, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी... सभी का समावेश हैं। खुलना, रंगपुर, राजशाही, बारीसाल, चिटगांव, सिल्हट.... बांग्लादेश के सभी विभागों में हिंदुओं पर हमले, अभी भी हो रहे हैं। मंदिर तोड़ना, मूर्तियों को ध्वस्त करना यह तो आम बात हो गई हैं। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, इस वर्ष दुर्गा पूजा के समय मात्र 35 दुर्गा पूजा मंडपों को अतिवादी मुसलमानों ने ध्वस्त किया। किंतु यह अत्यंत गलत आंकड़े हैं। बांग्लादेश के 'जातीय हिंदू महाजोट' (राष्ट्रीय हिंदू गठबंधन) के अनुसार, सैकड़ो दुर्गा पूजा मंडपों को पूर्णतया ध्वस्त किया गया है। मात्र 5 अगस्त से 31 अगस्त के बीच, 49 हाई स्कूल और कॉलेज के हिंदू शिक्षकों से जबरन, बलात् रूप से, अपनी नौकरी से त्यागपत्र लिए गए। चांदपुर जिले के फरीदगंज गांव के, गल्लक आदर्श डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हरिपद दास को मुस्लिम विद्यार्थियों ने अत्यंत घृणास्पद और अमानुष तरीके से अपमानित किया।

बांग्लादेश सरकार ने 5 अगस्त के बाद, एक ही महीने में 252 पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। बांग्लादेश में अब एक भी हिंदू पुलिस अधिकारी नहीं है। अकेले खुलना डिविजन का ही उदाहरण ले, तो वहां अब भी हिंदुओं पर हिंसा का तांडव चल रहा हैं। 5 अगस्त की रात को खुलना डिविजन के जशोर शहर के पास, बेजापारा गांव में रहने वाले, 200 हिंदू परिवारों पर जबरदस्त आक्रमण हुआ। उनके घर लूट गए। जिंदा व्यक्तियों के साथ घर जला दिए गए। महिलाओं को भगाकर ले जाया गया। पुलिस ने फोन भी नहीं उठाया। हिंदुओं पर हो रहे इस बिभत्स और नृशंस आक्रमण को, बांग्लादेश की पुलिस, मूकदर्शक बन देखती रही। 06 अगस्त को भी हिंदुओं पर आक्रमण जारी रहा। बागेरहाट सदर उपजिला में, वहां के लोकप्रिय सेवानिवृत्त स्कूल टीचर, मृणाल कांति चटर्जी को बेदर्दी से काटकर मार डाला गया। जेशोर शहर में उस दिन, 50 हिंदू घरों को लूटकर, उन्हें आग के हवाले किया गया।

सियासी गहमागहमी

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की सराहनीय पहल

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य सरकार पर निर्भरता कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में प्रयास करते हुए उन्होंने अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढ़िकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि श्याम बिहारी जायसवाल के इन फैसलों का राज्य के मुख्यमंत्री कैसे अमल में लाते हैं।

गीतामय होने को तैयार है मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इच्छानुसार पूरा प्रदेश गीतमय होने को तैयार है। प्रदेश में गीता महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रदेश में 8 से 12 दिसंबर तक होने वाले इस गीता उत्सव को लेकर विपक्षी दल के नेताओं और भाजपा नेताओं में कानाफूसी शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि एक तरफ जहां भाजपा गीता महोत्सव की बात कर रही है और इतना बड़ा आयोजन कर रही है उसी क्रम में अब सरकार को गीता के उपदेशों को अपनाते हुए राज्य की जनता के हित और जनकल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए। खैर, वाद-विवाद के बीच देखने वाली बात यह होगी कि अब मोहन सरकार क्या गीता के उपदेशों को अपनी कार्यशैली से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी या फिर यह सिर्फ एक आयोजन बनकर रह जायेगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

सुनने में आ रहा है कि GST से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है - आपकी जरूरत की चीजों पर GST बढ़ाने की योजना है।

जरा सोचिए - अभी, शादियों का सीजन चल रहा है। लोग कब से पाई-पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 से ऊपर के कपड़ों पर GST 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता, भारतीय राजनीति में त्याग की मूर्ति और भारत के लोकतंत्र को नई दिशा देने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

ईश्वर से आपकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।

बहुत-बहुत बधाई।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

देवेंद्र फडणवीसः पार्षद से सीएम तक का सफर

समता पाठक/जगत प्रवाह

देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण करने के साथ तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। राज्य के युवा नेता फडणवीस ने राजनीति में अपना मुकाम खुद अपने बलबूते हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले फडणवीस ने जब सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां जानिए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। देवेंद्र फडणवीस राजनीति में सक्रिय परिवार के दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके पिता बीजेपी से विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रह चुके हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत नागपुर में आरएसएस की शाखा से हुई थी। मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले उन्हें आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी से नेतृत्व का मौका मिला। देवेंद्र फडणवीस का परिवार मध्यमवर्गीय रहा है। उनके पिता के असामयिक निधन के कारण बने हालात ने उन्हें और उनके भाई को समय से पहले अधिक जिम्मेदार बना दिया। उनकी मां एक नौकरीपेशा महिला रही हैं। फडणवीस शहरी विकास में गहरी रुचि लेते रहे हैं। फडणवीस ने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ में टॉप किया था। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालांकि उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की। वे अध्ययन के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़कर पार्षद पद हासिल किया था। वे नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में पार्षद चुने गए थे। फडणवीस हमेशा अपने परिवार और कामकाजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी बैंकर हैं। उन दोनों की ही हिंदी फिल्म संगीत में, बॉलीवुड की फिल्मों में और घूमने में रुचि है। उनकी एक 15 साल की बेटी है। फडणवीस राज्य के उन कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से हैं जिनका अपना कोई अलग बिजनेस नहीं है। न तो उनके नियंत्रण में कोई निजी शिक्षण संस्थान है, न ही उनका किसी रियलिटी कंपनी, कोआपरेटिव संस्था आदि से कोई ताल्लुक है।

राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हर सर्दी, जब दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर जहरीली धुंध छा जाती है, तो यह क्षेत्र एक गैस चैंबर का रूप ले लेता है। वायु गुणवत्ता सूचनांक (AQI) 500 से अधिक चला जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते हैं, बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं और बुजुर्गों की हालत और भी खराब हो जाती है। लोगों का सुबह में सैर सपाटा बन्द हो जाता है। बावजूद इसके, जब राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे पर नजर डालते हैं, तो इस गंभीर समस्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राजनीतिक दलों ने भीषण प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के बजाए एक दूसरे पर सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम किया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के किए गए सारे उपाय बेअसर रहे। देश के सुप्रीम कोर्ट भी इन राजनीतिक दलों के सामने पस्त नजर आता है। कई चेतावनी के बावजूद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जनता भी अपनी निजी वाहनों का उपयोग बन्द नहीं करती। थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली देश का आठवां प्रदूषित शहर था। क्या यह हमारी सामूहिक असफलता है कि प्रदूषण जैसे संकट को हमने इतना सामान्य मान लिया है कि यह चुनावी मुद्दा बनने लायक भी नहीं रह गया? प्रदूषण एक खामोश हत्यारा की तरह है। दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय संकट बन चुका है। प्रदूषण एक खामोश हत्यारा की तरह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। एक आंकड़े के अनुसार 2019 में सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण से विश्व में 83.4 लाख लोगों की असमय मौत हुई थीं। थी। दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे खतरनाक कणों का स्तर सामान्य सीमा से कई गुना ऊपर पहुंच जाता है। इस समस्या की सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह किसी एक समुदाय, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चाहे वह झुग्गियों में रहने वाला मजदूर हो, जो जहरीली हवा में काम करने को मजबूर है, या अमीर वर्ग, जो एयर प्यूरीफायर और सील्ड गाड़ियों में रहकर भी सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण सभी पर समान रूप से वार करता है। सवाल उठना लाजमी है कि राजनीतिक दलों की चुप्पी इस विषय पर क्यों है? दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर राजनीतिक दलों की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह सवाल भी उठता है कि क्यों यह गंभीर समस्या उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं बनती ? एक कारण यह हो सकता है कि यह समस्या बेहद जटिल है। प्रदूषण का समाधान राज्यों के बीच सहयोग, केंद्र सरकार की सक्रियता, और विभिन्न विभागों के सामूहिक प्रयास की मांग करता है। यह एक दीर्घकालिक लड़ाई है, जिसमें त्वरित चुनावी लाभ मिलना मुश्किल है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इस मुद्दे को वोटर प्राथमिकता नहीं मानते। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी जैसे मुद्दे लोगों को तुरंत प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, प्रदूषण का असर धीमा और दीर्घकालिक है। यह शायद राजनीतिक दलों को इसे अनदेखा करने का मौका देता है। तीसरा कारण जनता का रवैया हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर के लोग शायद इतने लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। मास्क पहनना, एयर प्यूरीफायर खरीदना, और सर्दियों में कम बाहर निकलना उनकी दिनचर्या बन चुकी है। हमें मानना होगा कि यह एक एक मानवीय त्रासदी है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है, जो हर दिन इस जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। एक मां, जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। एक मजदूर, जो धुएं भरी हवा में दिनभर काम करता है। एक बुजुर्ग, जो खांसते-खांसते ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेने को मजबूर है। क्या यह जिंदगी है? क्या हम ऐसे भविष्य को स्वीकार कर सकते हैं, जहां हमारे बच्चे पार्क में खेलने के बजाय घरों में बंद रहने को मजबूर हों?

इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। किसानों को पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें सस्ती और प्रभावी मशीनें मुहैया कराना जरूरी है। अधिक सुलभ और आकर्षक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने लगाए जाने चाहिए। जब तक जनता इस मुद्दे को अपनी लड़ाई नहीं मानेगी, तब तक कोई भी नीति प्रभावी नहीं हो पाएगी। लोगों को समझना होगा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी भी है। राजनीतिक दलों को यह समझने की जरूरत है कि प्रदूषण का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि वोटरों के जीवन का मुद्दा है। इसे चुनावी एजेंडे में शामिल करना न केवल एक जिम्मेदार नेतृत्व की पहचान होगी, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ाएगा। दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसे हल नहीं किया जा सकता। बीजिंग जैसे शहरों ने इस दिशा में सफलता हासिल की है। अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो दिल्ली भी एक मिसाल बन सकती है। लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों को प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और जनता को अपनी आवाज उठानी होगी। अगर आज कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भविष्य जहरीली धुंध के अंधकार में खो जाएगा। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारे सपनों, और हमारी पहचान का प्रतीक है। इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हवा में जहर रहेगा, तो कोई भी वादा मायने नहीं रखेगा। अब समय है कि हम सभी इस दिशा में ठोस कदम उठाएं।

सेहत बनाने के लिए शानदार समय है सर्दियों का मौसम

सर्दियों का मौसम हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल होता है। इस मौसम में हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं। कैसे:

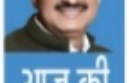

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

खान-पान का ध्यान रखें

* **गर्म और पौष्टिक भोजनः** सर्दियों में गर्म और पौष्टिक भोजन का सेवन करना बहुत जरूरी है। दालें, सब्जियां, फल, दही और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।
* **सूखे मेवेः** बादाम, काजू, अखरोट आदि सूखे मेवे विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
* **गर्म पानीः** दिन में कई बार गर्म पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन भी ठीक रहता है।
* **हर्बल चायः** अदरक, तुलसी और दालचीनी वाली चाय सर्दी-जुकाम से बचाती हैं और शरीर को गर्म रखती हैं।

योग, ध्यान और प्राणायाम

* **योगः** योगासन शरीर को लचीला बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और त्रिकोणासन जैसे आसन सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं।
* **ध्यानः** ध्यान करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है।
* **प्राणायामः** प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं।

कसरत करें

* **रोजाना व्यायामः** रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आप दौड़ना, चलना या योग भी कर सकते हैं।
* **खुले में व्यायामः** सर्दियों में धूप में थोड़ा समय बिताएं। धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है।

सर्दियों में इन सभी उपायों को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।

संविधान से धोखा है धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ

-प्रमोद भार्गव

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। न्यायमूर्ती पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को यह फैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के 24 नवंबर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था। लेकिन इस पीठ ने 21 पृष्ठीय फैसले में साफ किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिंदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मांगती है, तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है, वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं।

संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केंद्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं।

संविधान के अनुच्छेद-342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद- 341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकार्यता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिन्दू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा।

राज्यसभा में भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पुछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वे आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं ये लोग सरकारी नौकरियों के साथ-साथ संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध मत को मानने वाले लोग ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता रखेंगे। इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता रहेगी।' उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया था कि 'इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व को मानने वाले और इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच अधिनियम में पहले से ही स्पष्ट विभाजन रेखांकित है।' इस बयान से साफ हुआ था कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित और वृहद हिंदू धर्म के तहत आने वाले दलितों के बीच अंतर साफ है। यदि कालांतर में कार्यपालिका और विधायिका में बिना किसी बाधा के इस बयान पर अमल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हिंदुओं में धर्म परिवर्तन थमने का सिलसिला शुरू हो जाता और इससे राष्ट्रवाद को मजबूती मिलती। क्योंकि ज्यादातर ईसाई व इस्लामिक संस्थाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा घोलने के लिए विदेशी धन मिलता है।

2006 में केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, तब संविधान में 93वां संशोधन कर अनुच्छेद-15 में नया खंड-5 जोड़कर स्पष्ट किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे। लेकिन ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी निजी संस्थाओं पर लागू होंगे। चाहे उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता हो। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद-15 के खंड 3 व 4 के क्रम में ही किया गया था। इससे भी साफ होता है कि इन जातियों के जो लोग ईसाई या इस्लामिक संस्थाओं अर्थात अल्पसंख्यक संस्थाओं में धर्म परिवर्तित कर शिक्षा लेते हैं, उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी। साफ है, अब तक धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीनकर हकमारी कर रहे लोगों को वास्तव में आरक्षण के लाभ की पात्रता नहीं है। अतएव अनुसूचित जातियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बने अनुसूचित जाति के लोग केवल नौकरी के लिए फिर से धर्म परिवर्तन कर हिंदू नहीं बन सकते है। यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक सम्माजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

बीएचयू में यूपीएससी मास्टरी वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन

-अमित राय

जगत प्रवाह. वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में "यूपीएससी मास्टरी: सफलता के लिए रणनीतियाँ और तकनीकें" विषय पर एक वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन बीएचयू के डीन ऑफ स्टूडेंट्स द्वारा किया गया। बीएचयू के विभिन्न संकायों के 800 से अधिक छात्रों ने इस वर्कशॉप में भाग लिया, जिसका उद्देश्य उन्हें सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और रणनीतियों से लैस करना था। मुख्य वक्ता, प्रवीण प्रकाश, आईएएस ने यूपीएससी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञ सलाह साझा की। उन्होंने सरकारी नौकरी के महत्व और धैर्य और ईमानदारी के मूल्य पर बल दिया। उन्होंने एक मूल्यवान टिप भी साझा की, "04 साल की तैयारी के लिए 10 घंटे का नियम"। उनका आकर्षक और जानकारीपूर्ण सत्र उपस्थित लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। प्रो. अनुपम नेमा, डीन ऑफ स्टूडेंट्स और वर्कशॉप के समन्वयक ने इस आयोजन की शुरुआत की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद करने में इसके महत्व पर बल दिया। वर्कशॉप एक बड़ी सफलता थी और विश्वविद्यालय भविष्य में अपने छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर विकास को समर्थन देने के लिए ऐसे और आयोजन करने की योजना बना रहा है। (जगत फीचर्स)

अप्रेंटिसशिप मेला, प्लेसमेंट केम्प का आयोजन 9 दिसंबर को

-संवाददाता

जगत प्रवाह. कवर्धा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा, सरोदा बांध रोड़ तारो में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत आगामी 9 दिसंबर को प्रातः 9.30 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला में विभिन्न प्रतिष्ठानों को अप्रेन्टिस और प्लेसमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। समस्त शासकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ उक्त मेला में सम्मिलित होकर अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (जगत फीचर्स)

गाडरवारा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की माँग

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जनरल सेकेट्री मप्र ऑल इंडिया बेक वर्ड क्लासेस फेडरेशन मप्र एवं जिला अध्यक्ष मप्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला नरसिंहपुर ने मप्र शासन के स्कूली शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विद्यालय गाडरवारा में खोलने की माँग की। छात्रों और जनहित को देखते हुए गाडरवारा क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय विद्यालय अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों किसानो गरीब लोगों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिले। पचमढ़ी, नरसिंहपुर, केंद्रीय विद्यालय और बोहानी में नवोदय विद्यालय हैं केवल गाडरवारा क्षेत्र जो आपकी विधानसभा क्षेत्र भी है। जनता को आशा है और माँग भी आपसे करते हैं गाडरवारा क्षेत्र को केंद्रीय विद्यालय खोला जाये। (जगत फीचर्स)

एनएसएस एवं रेड रिबन क्लब के तत्वाधान में जनजागरूकता रैली का आयोजन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी में विश्व एड्स दिवस (01 दिसम्बर 2024) के अवसर पर एवं रेड रिबन क्लब के अंतर्गत आयोजित साप्ताहिक गतिविधियों में आज दिनांक 06 दिसम्बर 2024 को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश दुबे के मार्गदर्शन में एड्स जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी शिवलाल अहिरवार ने रैली की थीम ''अधिकारों की राह अपनाएं-मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार'' पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य एचआईव्ही एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। एनएसएस एवं रेड रिबन क्लिब के तत्वाधान में होने वाली साप्ताहिक गतिविधियों के अंतर्गत महाविद्यालय में निबंध, पोस्टर निर्माण, प्रश्नमंच प्रतियोगिता एवं व्याख्यान/परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. ओमना सेनानी, डॉ. अभिषेक गोयल, डॉ. आशीष जैन, डॉ. सारांश राजोरिया, राजेश गिरवाल, प्रेमनारायण साहू, पंकज प्रजापति एवं स्वास्थ्य विभाग से आईसीटीसी काउंसलर अजय ठाकुर, लैब तकनीशियन सुखराम बारिया तथा एनएसएस/रेड रिबन क्लब के स्वयंसेवक व अधिक संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

बस्तर के तोकापाल की सुश्री बबीता नाग ने मुख्यमंत्री को बांधा निरामय सूत्र

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। एम्स रायपुर के आडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया एवं कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी तथा उनका उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से लड़ाई लड़ी और आज स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बस्तर के तोकापाल की रहने वाली बबीता नाग जो कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से पीड़ित थीं। इन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करायी और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए समय पर दवाइयों और पोषण आहार का सेवन किया। इसकी वजह से बबीता आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। बबीता ने अपने स्वस्थ होने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया है जिनकी पहल की वजह से वो टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूक हो सकीं और समय पर अपना इलाज कराया। मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद देने के लिए बबीता आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित थीं। उन्होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने हाथों से निक्षय निरामय सूत्र बांधा और प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए आभार प्रकट किया।

डॉ. हिमाद्री सिंह को एनबीआरसीओएम-2024 में सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल।,एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में, संस्थान ने शोध और चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। उनके मार्गदर्शन में एम्स भोपाल के जैव रसायन विभाग की डॉ. हिमाद्री सिंह को 5वें साइंस कॉन्क्लेव-कम-नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च कॉम्पिटिशन में सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन 01-03 दिसंबर 2024 को एम्स दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन द्वारा सोसाइटी ऑफ यंग बायोमेडिकल साइंटिस्ट्स, इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया गया। प्रो. सिंह ने डॉ. सिंह की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा, "यह पुरस्कार एम्स भोपाल में नवाचार और अनुसंधान उत्कृष्टता की भावना का प्रतीक है। डॉ. हिमाद्री सिंह का अस्थमा के लक्षित उपचारों पर किया गया कार्य, इस बीमारी से पीड़ित लाखों लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। इस तरह का अग्रणी अनुसंधान रोगी देखभाल को बदलने और स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार करने में जैव चिकित्सा विज्ञान की भूमिका का प्रमाण है।" डॉ. सिंह का यह शोध, एम्स भोपाल के जैव रसायन विभाग के प्रो. अशोक कुमार और एम्स बीबीनगर के डॉ. रोहित सलूजा के मार्गदर्शन में किया गया। इस अध्ययन में बायोइन्फॉर्मेटिक्स आधारित ड्रग रिपरपसिंग विधियों का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से दो ऐसे यौगिकों की पहचान की गई, जो अस्थमा की रोगजनन में शामिल प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स के स्राव को रोक सकते हैं। इन यौगिकों को मानव मास्ट सेल लाइनों का उपयोग करके इन विट्रो प्रयोगों के माध्यम से सत्यापित किया गया। यह शोध IL-33/ST2 सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक करने की क्षमता को प्रमाणित करता है, जो अस्थमा के इलाज का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

(जगत फीचर्स)

उद्योगपतियों को सीएम का हर मदद देने का भरोसा, बोले नर्मदापुरम जिले में उद्योगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 07 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन से पहले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगपतियों का स्वागत है। हमारी मंशा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबसे पहले स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और वर्तमान में संचालित उद्योगों को विस्तार करने में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। नर्मदापुरम जिले उद्योगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए यहां उद्योगपतियों को उद्योग लगाने आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सहायता से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। आप सभी आगे आएं, नए उद्योग स्थापित करें और युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश के विकास में सहभागी बनें।"

स्थानीय उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि सबसे पहले स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसके बाद राज्य, राष्ट्रीय और अंततः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपतियों को अवसर दिया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसे हमने बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया है।

नर्मदापुरम जिले में उद्योगों के विस्तार और निवेश की नई संभावनाएं

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिले में।उद्योगों की बड़ी संभावनाएं हैं। सीएम ने नर्मदापुरम के कई उद्योगपतियों से व्यक्तिगत चर्चा भी की। उन्होंने हरदा के राइस।मिल मालिकों से अपने उद्योगों का विस्तार करने का आग्रह किया और मूंग दाल मिल के मालिक जसप्रीत सिंह से कहा कि उनके पास अतिरिक्त मूंग हो तो उसे उज्जैन के व्यापारियों को भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने एमएसएमई के माध्यम से उद्योग शुरू करने वाली ज्योति अग्रवाल और कैटल फीड इंडस्ट्री के मालिक नरेंद्र सिंह तोमर की सफलता की सराहना की। निर्मल मसाला इंडस्ट्री के मालिक ने बताया कि उनकी मसाला मिल 42 प्रकार के मसालों का उत्पादन करती है, जो 12 जिलों में वितरित किए जाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, "आपके मसाले एमडीएच मसालों की तरह प्रसिद्ध हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।"

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में नर्मदापुरम बन सकता है अव्वल

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदापुरम क्षेत्र में कृषि उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के साथ अन्य सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे अपने मौजूदा व्यवसायों के साथ नए उद्योग क्षेत्रों में भी निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके सहयोग से ही क्षेत्रीय विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ओर समग्र प्रयास

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नर्मदापुरम के बाद जनवरी में शहडोल में भी क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इन सम्मेलनों की कड़ी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने यूके और जर्मनी दौरे का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से प्रदेश को 78,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।

प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। उनके प्रयासों से ही रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हम प्रदेश के सभी उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। RIC नर्मदापुरम के माध्यम से संभावित क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी उद्योगपतियों को सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण देते हुए कहा कि यह आयोजन निवेश और विकास के अवसरों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मंच प्रदान करेगा। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने 07 दिसंबर को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उज्जैन जिले के प्रभारी एवं कौशल विकास एवं रोजगार राज्य स्वतंत्र प्रभार गौतम टेंटवाल भी वीसी में शामिल हुए।

(जगत फीचर्स)

आखिरकार क्यों कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस से भाजपा में जाने की प्लांट की जाती हैं खबर, किसको है कमलनाथ से खतरा?

बंटी साहू और भाजपा ने 7 महीने में छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट मॉडल पर लगाया बट्टा, नहीं हो रहा अब छिंदवाड़ा का विकास

क्या कांग्रेस के विदर्भ में हार के पीछे जीतू, भूपेश और उनके चेलों की है प्रमुख भूमिका?

महाराष्ट में कांग्रेस को जिता सकते थे कमलनाथ

क्या 2028 में कांग्रेस की आखिरी उम्मीद केवल कमलनाथ हैं?

-विजया पाठक

अभी हाल में ही हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद एक निष्कर्ष यह सामने आया है कि पार्टी को आज एक तजुर्बेकार नेता की जरूरत है जो अपने अनुभव और संगठन दक्षता से पार्टी को स्थिर कर सके। बड़ा सवाल यह है कि जब भी कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ को कुछ नई जिम्मेदारी देने की योजना पर काम करता है, तो मीडिया में आखिर कौन साजिशकर्ता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने का भ्रम फैलाते हैं और यह किसके द्वारा फैलाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से कम से कम 6-7 बार ऐसी खबरें आई होंगी जिसमें कमलनाथ या उनके परिवार का भाजपा में शामिल होने की बात कही गई थी। लोकसभा चुनावों के पहले तो इसको फैलाकर छिंदवाड़ा की जनता को भी भ्रम में डालने की कोशिश की गई थी। कमलनाथ में राजनीति एक बड़े उद्देश्य से आए हैं जिसका कुर्सी और पद कोई वास्ता नहीं है। जिन्हें स्वयं इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा माना, कोई 45 वर्षों से देश और कांग्रेस पार्टी की सेवा कमलनाथ ने निस्वार्थ तरीके से एक बेटे के समान की है, ऐसे नेता के खिलाफ आखिर ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है। शायद इसका एक कारण यह तो नहीं कमलनाथ को कोई प्रमुख जिम्मेदारी मिल जाए तो पार्टी कांग्रेस को कमलनाथ उभार सकें। कमलनाथ ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई पद का मोह नहीं है, इसकी बानगी विजयपुर चुनाव में देखने को मिली जहां टीम कमलनाथ ने मोर्चा संभाल कर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलवा दी। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है।

कमलनाथ की छिंदवाड़ा डेवलेपमेंट मॉडल पर भाजपा और उनके सांसद ने लगाया बट्टा

पिछले दिनों मध्यप्रदेश ने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे किये। देखा जाये तो स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष से अधिक के काल में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में आज भी पिछड़े राज्यों में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति और उससे जुड़े लोग। जब भी जिस पार्टी को भी प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला उसने सिर्फ अपने हितलाभ से जुड़े फैसले लिये और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मप्र भाजपा के पिछले दो दशक। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर अब तक जो भी योजनाएं बनी उनमें कहीं न कहीं केंद्र में राजनैतिक दल, राजनीति से जुड़े लोग या फिर प्रभावी समूह रहे हैं। यही कारण है कि आज भी मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की सूची में नंबर वन नहीं बन पाया है। वहीं, इसी राज्य का एक जिला है छिंदवाड़ा। वर्षों तक विकास की योजना से कोसों दूर रहा। छिंदवाड़ा जिले का कायाकल्प लगभग चार दशक पहले आरंभ हुआ। उसका कारण यह भी था कि छिंदवाड़ा और वहां की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के रूप में एक ऐसा नेता मिला जिसने समाज सेवा को ही अपना धर्म समझा और राजनीति करने के बजाय उन्होंने जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में कार्य किया।

अथक परिश्रम और समर्पण का प्रतीक हैं कमलनाथ

आज जब हम छिंदवाड़ा जिले की ओर बढ़ते हैं तो एक अद्भुत और अकल्पनीय नजारा देखने को मिलता है। पुराने लोगों से चर्चा करने में मालूम चलता है कि वे खुद आश्चर्य में है कि किस तरह से एक राजनेता ने अपने अथक परिश्रम और मेहनत से एक बीमारू और पिछड़े जिले को देश का मॉडल जिला बनाकर खड़ा दिया। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, अधोसंरचना, पर्यटन हर क्षेत्र में क्रमवार ढंग से कमलनाथ ने कार्य किया और पिछले चार दशकों में देश के आगे छिंदवाड़ा नाम का एक आदर्श मॉडल खड़ा कर दिया। यह मॉडल केवल नाम का नहीं है बल्कि इसने अपनी कार्यशैली से देश में अपनी विशिष्ट पहचान भी स्थापित की है।

धीर-गंभीर नेता के परिश्रम से बना मॉडल

कमलनाथ बेहद धीर-गंभीर और संजीदा राजनेताओं में से एक है। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं बल्कि समाज सेवा उनका पहला धर्म है। उन्होंने समाज सेवा के पांच दशकों में जनता के दिलों पर अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक लोगों के मन मस्तिष्क में बनी हुई है। अपने कार्य पर फोकस, भविष्य की योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन, बेतरतीब बातों पर बयानबाजी से बचना यह उनकी विशिष्टता है। राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो कमलनाथ वे नेता है जिन्होंने गांधी परिवार के हर व्यक्ति के साथ पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य किया। फिर चाहे वह इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह हो या फिर राहुल गांधी। आज भी जब कांग्रेस किसी परेशानी में होती तो निश्चित तौर पर कमलनाथ को याद किया जाता है और उनसे सलाह मशवरा होता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पिछले दिनों कमलनाथ और राहुल गांधी की बंद कमरे में हुई बैठक। इन वर्षों के दौरान, छिंदवाड़ा एक शांत और साधारण शहर से व्यापक सड़क और रेल नेटवर्क और एक मॉडल रेलवे स्टेशन के साथ उद्योगों के केंद्र में बदल गया।

कौशल विकास केंद्रों की स्थापना

कमलनाथ ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई), परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (एटीडीसी) और आईएल एंड एफएस कौशल विकास निगम जैसे विभिन्न कौशल विकास केंद्रों की स्थापना में भी मदद की। छिंदवाड़ा में सेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रभारी के अनुसार ये केंद्र युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में मदद करने के लिए टीसीएस, एचसीएल और इंफोसिस जैसे आईटी दिग्गजों के साथ भी सहयोग करते हैं। उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के स्थानीय कार्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधन करने वाले शिवगोपाल के अनुसार, इन पहलों से न केवल 36.82 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले छिंदवाड़ा को, बल्कि आसपास के आदिवासी जिलों बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी को भी मदद मिली। उन्होंने कहा, कई आदिवासी छात्र कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए छिंदवाड़ा आते हैं।

जिला बनाने में की मदद

2019 के आम चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्य की 29 संसदीय सीटों में से 28 पर जीत हासिल की। हालांकि, छिंदवाड़ा कांग्रेस के साथ मजबूती से बना रहा, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भाजपा के आदिवासी चेहरे नाथनशाह कवरेती के खिलाफ 37,536 वोटों के अंतर से सीट जीती। 2019 के उपचुनाव में भी कमलनाथ ने भाजपा के विवेक साहू को 24,612 वोटों से हराकर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट जीती। 2024 में भितरघात और भ्रम से बंटी साहू और भाजपा ने भले ही छिंदवाड़ा सीट जीत ली हो पर उसके बाद छिंदवाड़ा के प्रोग्रेसिव डेवलेपमेंट पर बट्टा बिठा दिया। जहां सांसद बंटी साहू छिंदवाड़ा के विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी जिले से अपना मुंह मोड़ लिया है।

विदर्भ में कमलनाथ को मिलती जिम्मेदारी तो परिणाम कुछ और होते

हाल ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान विदर्भ क्षेत्र में हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने यहां के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और मप्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जैसे अनुभवहीन नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इनके कारण इस क्षेत्र में कांग्रेस का बंटाढार हो गया। यदि इस क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ को जिम्मेदारी मिलती तो आज परिणाम कुछ और होते। क्योंकि विदर्भ क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और हम जानते हैं कि कमलनाथ का उद्योगपतियों से और वहां की जनता से कैसा जुड़ाव रहा है। एक राजनेता के अलावा कमलनाथ उद्योगपति भी हैं और उद्योगों से जुड़े लोगों से उनकी सहानुभूति हमेशा रही है। कमलनाथ का वहां सक्रिय होना निश्चित ही पार्टी के हित में होता।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)